भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 281*

21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ई-बसों की तैनाती"

***281. श्री रवनीत सिंह बिट्टू:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ई-बसों की तैनाती किए जाने की गति अब तक उत्साहजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में राज्य सरकारों द्वारा ई-बसों के और अधिक क्रयादेश दिए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाने सहित कोई उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

<u>विवरण</u>

"ई-बसों की तैनाती" के संबंध में दिनांक 21.03.2023 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत श्री रवनीत सिंह बिट्टू के तारांकित प्रश्न संख्या 281 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं। देश में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ई-बसों की तैनाती की गति उत्साहजनक रही है। अब तक विभिन्न राज्य परिवहन इकाइयों (एसटीयू) ने 3,738 ई-बसों के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किए हैं और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने 3,472 ई-बसों के लिए एकत्रीकरण मॉडल शुरू किया है। इस प्रकार, इस स्कीम के अंतर्गत 7,090 ई-बसों के लक्ष्य की तुलना में कुल 7,210 ई-बसें संस्वीकृत की गई हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि संस्वीकृत 7,210 ई-बसों में से 2435 ई-बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं।

(ग) से (ङ): भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित 7,090 ई-बसों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, सीईएसएल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) के तहत 50,000 ई-बसों की चरणबद्ध तैनाती के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

***